

2



छठ में 14 नवंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी

3



ऑल्लेम्क में उल्लेखनीय उपलब्धि

5



पेरक राजनैतिज्ञ के रूप में विशिष्ट पहचान

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 28

प्रति सोमवार, 18 नवंबर 2024

मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

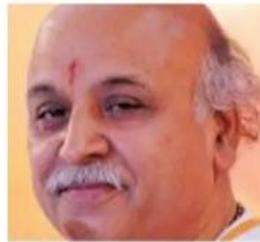
संघ चाहता है संजय जोशी, प्रवीण तोगड़िया और योगी आदित्यनाथ में से कोई एक बने बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष

वर्ष 2025 के शुरुआत में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है। अटकले हैं कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में हो सकता है। बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, यह सवाल पार्टी के अंदर और बाहर बढ़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बीते चुनावों के कारण बढ़ाया गया था, लेकिन अब संगठन में नए अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द हो सकती है। दिसंबर तक बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव पूरे हो जाएंगे, उसके बाद ही

कवर स्टोरी

-विजया पाठक

एडिटर



इन तीनों नामों में मोदी-शाह जैसे नेताओं की फूल रही सांसें

नये राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया प्रारंभ हो जायेगी। नये राष्ट्रीय अध्यक्ष की तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन जो अटकलें चल रही हैं उसमें राष्ट्रीय

स्वयंसेवक संघ यानि आरएसएस की दखलअंदाजी को ज्यादा तवज्जो दिये जाने की चर्चा है। संघ चाहता है कि संजय जोशी, प्रवीण तोगड़िया और योगी

आदित्यनाथ में से कोई एक बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जिसके लिए संघ ने बिसात बिछाना शुरू कर दी है। इस बिसात में इस बार संघ पूरी ताकत के

साथ खड़ा है। क्योंकि संघ को लगता है कि जिस विचारधारा पर देश को ले जाना है उसमें यह तीन नाम ही पूरी तरह फिट बैठ रहे हैं। हम जानते हैं कि बीजेपी मूलतः संघ की राजनीतिक इकाई है, संघ की सर्वोच्च संस्था है, लेकिन 2019 के बाद से उसकी सर्वोच्चता पर सवाल उठे हैं और इसे संघ फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच साल 2019 के बाद टकराव ज्यादा गहरा हुआ है, जिसके चलते स्थितियां पेचीदा हुई हैं। अनुच्छेद 370, समान नागरिक संहिता और राम मंदिर मूलतः संघ के एजेंडे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी कर्तारता बन गए, क्योंकि हर जगह वे ही दिखाई दे रहे हैं। (शेष पेज 7 पर)

सेकेण्ड स्टोरी छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति 2024-29

औद्योगिक विकास को गति देने में जुटी साय सरकार

प्रदेश को मिलेगी आर्थिक गति, रोजगार के अवसर सृजित होंगे

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ सरकार ने "अमृतकाल: छत्तीसगढ़ विजन/2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई औद्योगिक नीति 2024-29 लागू करने की घोषणा की है। जिसमें औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और आर्थिक समृद्धि को हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में विकास को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार नई औद्योगिक नीति को लागू करने जा रही है। इसके तहत छोटे और मझोले उद्योगों को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिए



जाने की योजना है। छत्तीसगढ़ में निवेश करने पर कई तरह की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को एक समृद्ध और सतत आर्थिक विकास वाले राज्य में बदलना है। यह नीति राज्य में औद्योगिक गतिविधियों

को बढ़ावा देकर विकास की नई राह खोलेगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार निवेशकों को लुभाने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए विष्णुदेव साय सरकार नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आई है। इसमें निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई चीजें हैं। उद्योगों को प्रदेश में सब्सिडी दी जाएगी। नीति के अनुसार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पाने के लिए उद्योगों में राज्य के मूल निवासियों को तीन श्रेणियों में रखना अनिवार्य किया जा सकता है। अकुशल कर्मचारियों/श्रमिकों

के मामले में शत प्रतिशत, कुशल कर्मचारियों के मामले में कम से कम 70% और प्रबंधन/संचालन कर्मचारियों के मामले में कम से कम 40% पदों पर मूल निवासियों की भर्ती संभव है। इसके अलावा उद्योग राज्य शासन के समन्वय से सीएसआर फंड खर्च कर सकेंगे। दरअसल, नई नीति में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए लेब बनाने पर जोर है। साथ ही बंद एवं बीमार उद्योगों के पुनर्वास के लिए पैकेज देने का भी निर्णय लिया गया है। (शेष पेज 6 पर)

मध्यप्रदेश की मोहन सरकार का 11 महीने के कार्यकाल का ऐतिहासिक फैसला महिलाओं को शासकीय नौकरियों में 35% आरक्षण

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश ने सफलता की अनेकों

कहानियां लिखकर राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई है। राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे सतत प्रयासों ने महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाया है। मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने शासकीय सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया



है। साथ ही पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की है। उद्यमी महिलाओं को राज्य सरकार 02 प्रतिशत दर से ऋण भी उपलब्ध करा रही है। आजीविका मिशन के माध्यम से 40 लाख से अधिक महिलाओं को स्व-रोजगार से जोड़ा गया है। दरअसल पिछले दिनों मध्यप्रदेश में मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। यह बैठक 05 नवंबर 2024 को हुई। (शेष पेज 6 पर)

छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से 31 जनवरी तक होगी धान की खरीदी

सीएम ने किया शुभारंभ, किसानों को मिलेगा 72 घंटे में भुगतान

-संवाददाता

उगत प्रवाह. रायपुर। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और धान राज्य की प्रमुख फसल है। लाखों की संख्या में किसान धान का खेती करते हैं। सरकार धान को सरकारी मूल्य पर खरीदती है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी महापर्व का आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बालोद जिले के भांडागांव (बी) स्थित धान खरीदी केंद्र से इस महापर्व की शुरुआत की। 14 नवंबर से लेकर 31 जनवरी 2025 तक पूरे राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने केंद्र में पहुंचकर इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन और अन्य उपकरणों का पूजन किया और वहां मौजूद किसानों का माला पहनाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर किसानों को बधाई

और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह महापर्व किसानों की मेहनत और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। किसानों के चेहरों पर संतोष की झलक देखते ही बन रही थी। इस उपार्जन केंद्र पर पहले दिन कुल 6 किसानों का

शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी, शाहीद बिरसा मुंडा और गहिरा गुरु के तैल चित्रों पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से की गई। राज्य में 31 जनवरी 2025 तक पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की जाएगी। सरकार ने यह सुनिश्चित



किया है कि किसानों को उनकी फसल का भुगतान 72 घंटे के भीतर उनके बैंक खातों में किया जाएगा। इस बार राज्य में कुल 2,739 धान खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में 27,01,109 पंजीकृत किसानों ने 34,51,729 हेक्टेयर भूमि

टोकन काटा गया, जिससे धान खरीदी का काम सुचारू रूप से शुरू हो गया। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने गुण्डरदेही विकासखंड के ग्राम मोहंदीपाट में 30 लाख रुपये की लागत से निर्मित जिला सेवा सहकारी बैंक की नई शाखा का भी उद्घाटन किया। कार्यक्रम की

पर धान की बुआई की है, जिसमें से 1,35,891 किसान नए पंजीकृत हैं। सरकार की यह पहल किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। (जगत फीचर्स)

प्रत्येक शुगर मिल के पास लगाया जाए शासकीय तुलाई काटा

-बद्रीप्रसाद कौरव

उगत प्रवाह. जलसिंहपुर। मद्र जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बेक वर्ड क्लासेस फेडरेशन मद्र नरसिंहपुर जिला के किसानों की हालत खराब है। जहां उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा तो दिला या जाता है मगर वह भरोसा मात्र होता है, जिसका परिणाम है जिले के गन्ना किसानों को हर वर्ष शुगर मिलों में शोषित होते हुए अपना गन्ना बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिलों की शुगर मिलों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले तोल कार्टों पर किसान के गन्ने की तुलाई किस तरह से होती है इस बात की सत्यता किसी को जानकारी ना हो, इसको किसानों की मजबूरी कहीं जावे जिसके चलते चाहकर भी अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाते और जो किसान अपनी आवाज बुलंद करने

का प्रयास करता है उनकी आवाज को दबाने के लिए शुगर मिल मालिक अनेक प्रकार के प्रयास करने से नहीं चूकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिले के किसानों द्वारा शुगर मिलों के संचालन की शुरुआत होने के पहले ही शासन प्रशासन से मांग की जा रही है कि शुगर मिलों में गन्ने की खरीद का कार्य शुरू होने के पहले ही प्रत्येक शुगर मिल के पास शासकीय तोल कार्टों को स्थापित किए जाये जिससे किसान शोषण होने से बच सकें, क्योंकि जब गन्ने का सीजन शुरू हो जाता है उस दौरान मिलों के संचालक पूर्ण मनमानी पर उतारू होकर किसानों के गन्ने की तुलाई में लापरवाही करने से नहीं चूकते, समय रहते शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देकर किसानों के हित के लिए कार्य करे। (जगत फीचर्स)

अवैध नशे कारोबारियों की धरपकड़ अभियान में 2 किलो गांजा के साथ बाइक सवार 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार



-कैलाशचंद्र जैन

उगत प्रवाह. विदिशा। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवाना की निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे एवं नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह के मार्गदर्शन में थाना सिविल लाइन पुलिस विदिशा की टीम को 02 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। 08 नवंबर 2024 की दरमियानी रात को थाना सिविल लाइन पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गद्दी रायसेन तर्फ से बाइक सवार दो व्यक्ति विदिशा तर्फ अवैध मादक पदार्थ गाजा लेकर आ रहे हैं एवं किसी बाहरी तस्कर को देने वाली है, सूचना पर थाना सिविल लाइन पुलिस

टीम रवाना होकर मुखबिर के बताए स्थान पर घेराबंदी कर बाइक सवार दो व्यक्तियों को एक थैले के साथ पकड़ा, एवं व्यक्तियों के पास मिले थैले की विधिवत तलाशी ली गई, जिसमें 02 किलो अवैध गाजा होना पाया गया, अवैध गांजा को विधिवत जप्त किया गया एवं आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर थाने लाया गया एवं आरोपियों के विरुद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी सिविल लाइन द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ के कारोबारियों के विरुद्ध थाना स्तर पर कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। (जगत फीचर्स)

रायपुर दक्षिण विस उपचुनाव

कम मतदान से बढ़ रही उम्मीदवारों की धड़कनें

-संवाददाता

उगत प्रवाह. रायपुर। छत्तीसगढ़ की रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा सीट पर वोटिंग हो गई है। चुनाव का परिणाम 23 तारीख को आयेगा। उपचुनाव में 50 फीसदी से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया। कम मतदान से दोनों उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। कम मतदान का अर्थ हुआ है कि लोगों ने चुनाव को महत्व नहीं दिया है और पासा किसी भी तरफ जा सकता है। उपचुनाव में 30 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं लेकिन मुख्य मुकामला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने रायपुर के पूर्व सांसद और पूर्व महापौर सुनील सोनी को चुनावी मैदान में उतारा है जबकि कांग्रेस ने

युवा चेहरा आकाश शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में कम वोटिंग को लेकर दोनों ही दलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि इसके बाद भी दोनों पार्टियां अपनी-अपनी जीत के दावे कर रही हैं। पिछले साल हुए राज्य विधानसभा चुनाव में रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा सीट में 60.2 प्रतिशत मतदान हुआ था। तब बीजेपी उम्मीदवार बुजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस उम्मीदवार को करारी शिकस्त दी थी। इस सीट को बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है लेकिन कम वोटिंग के बाद इस सीट को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। उपचुनाव में कम वोटिंग के कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। राज्य

में पिछले कुछ चुनावों का ट्रेंड देखें तो 60 फीसदी से वोटिंग में बीजेपी को नुकसान जबकि कांग्रेस को फायदा होता है। हालांकि इस बार जिस सीट पर उपचुनाव था वहां कांग्रेस ने निष्क्रिय बनाम सक्रिय का मुद्दा उठाया था। कांग्रेस ने पूरे कैंपेन में दावा किया कि बीजेपी उम्मीदवार रायपुर के सांसद रहते हुए सबसे निष्क्रिय रहे हैं। वहीं, आकाश शर्मा युवा और सक्रिय उम्मीदवार हैं। **बीजेपी ने भी किया जीत का दावा** वहीं, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी जीत का दावा किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस सीट से बीजेपी जीतते आ रही है और एक बार फिर से जीत दर्ज करेगी। (जगत फीचर्स)

एमएस भोपाल के नेत्र विज्ञान विभाग की एमपी स्टेट ऑप्थैल्मिक सम्मेलन में उल्लेखनीय उपलब्धि

-अर्चना शर्मा

जगत प्रवाह. भोपाल। एमएस भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रो. (डॉ.) अजय सिंह के मार्गदर्शन में, नेत्र विज्ञान विभाग ने हाल ही में सम्पन्न एमपी स्टेट ऑप्थैल्मिक सोसाइटी सम्मेलन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कई पुरस्कार जीते हैं। प्रो. भावना शर्मा के निर्देशन में विभाग के कई चिकित्सकों ने इस सम्मलेन में भाग लिया और विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार जीते। प्रो. सिंह ने इस उपलब्धि पर कहा, "एमएस भोपाल का नेत्र विज्ञान विभाग नवाचार, उत्कृष्टता और समर्पण का प्रतीक बन गया है। ऐसी उपलब्धियां न केवल एमएस भोपाल की प्रतिष्ठा को बढ़ाती हैं, बल्कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अनुसंधान और उपचार में नए मानक स्थापित करती हैं। हमें गर्व है कि हमारे



छात्र और संकाय सदस्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी पहचान बना रहे हैं।" सम्मेलन में एमएस भोपाल के विभाग के नेत्र विज्ञान विभाग की

एडिशनल प्रोफेसर डॉ. सरोज गुप्ता को सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार उन्हें आंखों के आर्बिट और ऑकुलोप्लास्टी पर उनके शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए दिया गया। बाल चिकित्सा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फ्री पेपर के लिए डॉ. ख्याति निरापुरे के शोध पत्र "पैटर्न ऑफ रिफ्रेक्टिव एरर्स इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप एट ए टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर इन सेंट्रल इंडिया" को चयनित किया गया। इसके अतिरिक्त, "चुनौतियों से भरी परिस्थितियों में कॉर्नियल चोटों में विजुअल आउटकमस को ऑप्टिमाइज करना: एक पुरानी समस्या पर विजय" विषय पर प्रस्तुति देने के लिए डॉ. निकिता आहूजा को कुमुद वी ए जोशी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी पुरस्कार के पीजी श्रेणी में, डॉ. राधिका

अग्रवाल ने "एक्यूट सेंट्रल सिरस कोरियोरेटिनेपैथी में तनाव स्तर और ओसीटी आधारित रेजोल्यूशन पैटर्न का मूल्यांकन - एक नई दृष्टिकोण" विषय पर अपने शोध के लिए पुरस्कार जीता। इसके साथ ही, डॉ. राधिका अग्रवाल को क्लिनिकल फोटोग्राफ की पहचान के लिए कक्षा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नेत्र विज्ञान विभाग के लिए यह बीता पखवाड़ा कई उपलब्धियों से भरा रहा, जिसमें राज्य और राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों में "कॉर्निया" और "टीचर्स ऑफ टर्मिन" श्रेणी के तहत कई पुरस्कार प्राप्त हुए। ये पुरस्कार एमएस भोपाल के चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान, और रोगी देखभाल के नए मानक स्थापित करने के प्रयासों को और अधिक मजबूत बनाते हैं। (जगत फीचर्स)



संतुलित औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नर्मदापुरम में आरआईसी

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के संतुलित विकास के लिये निरंतर सभी अंचलों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं। अगली आरआईसी आगामी 07 दिसम्बर को नर्मदापुरम में हो रही है। नर्मदापुरम क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग बहुतायत में हैं। नर्मदापुरम, हरदा, और होशंगाबाद में पहले से स्थापित उद्योगों के साथ-साथ कृषि प्रसंस्करण, सोयाबीन तेल, मसाला उत्पादन और दुग्ध प्रसंस्करण जैसे उद्योग यहाँ की आर्थिक गतिविधियों का मुख्य आधार हैं। इसके अतिरिक्त, क्षेत्र की खनिज संपदा का उपयोग कर निर्माण और अन्य उद्योगों से भी स्थानीय विकास को गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं। छठवीं आरआईसी का आयोजन 7 दिसंबर 2024 को नर्मदापुरम के डिवीजनल आईटीआई में किया जाएगा। पिछली पांच रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के अनुभवों से प्रेरित होकर, इस कॉन्क्लेव का नर्मदापुरम क्षेत्र में आयोजन उद्योगों की वृद्धि, निवेश को संभावनाओं और रोजगार सृजन के अवसरों को बढ़ाने के लिये किया जा रहा है। नर्मदापुरम आरआईसी में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, MSME और पर्यटन क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रयासों से प्रदेश में एक उद्योग-हितैषी वातावरण बना है, जिससे प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। (जगत फीचर्स)

बक्सर:
जिला स्तरीय
रबी महामियान
का आयोजन

फसल अवशेष के प्रबंधन हेतु सजगता की जरूरत

-अमित राय
जगत प्रवाह. बक्सर। जिला पदाधिकारी बक्सर, अंशुल अग्रवाल के द्वारा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अधिकरण (आत्मा) बक्सर के तत्वाधान में नगर भवन बक्सर में एक दिवसीय जिला स्तरीय रबी महामियान का दीप प्रज्वलित कर आयोजन का शुभारंभ किया गया। इस दौरान आत्मा बक्सर द्वारा प्रकाशित रबी फसल की उत्पादन तकनीकी पुस्तिका का विमोचन जिला पदाधिकारी बक्सर द्वारा किया गया। जिला पदाधिकारी ने बताया कि बिहार राज्य में 11 प्रतिशत पराली बक्सर जिले में जलाई जा रही है। इस महानजर पराली प्रबंधन पर गंभीरता से नियंत्रण करने की आवश्यकता है। कृषि विभाग के प्रसार कर्मी पराली जलाने से होने वाले नुकसान को किसानों के

बीच जानकारी साझा करे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत कृषि विभाग की सभी योजनाओं में पारदर्शी तरीके से अनुदान वितरित किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पराली जलाने में सलित कृषकों पर कार्रवाई कर कृषि विभाग द्वारा संचालित किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। उप विकास आयुक्त बक्सर डॉ. महेन्द्र पाल ने कहा कि खेती में आधुनिक तकनीक को जोड़कर उत्पादकता बढ़ाने की जरूरत है। इस दिशा में सभी प्रसार कर्मी किसानों के बीच तकनीक को हस्तांतरण करें। अपर समाहर्ता बक्सर ने कहा कि हमारा देश कृषकों का देश है। किसान कृषि को जीविकोपार्जन का साधन बनाकर उत्पादकता को बढ़ाए तो किसानों की आर्थिक स्थिति को

सुधारा जा सकता है। प्रशिक्षु आईएएस प्रतीक्षा सिंह ने बताया कि इस जिले की जलवायु रबी फसल हेतु अनुकूल है। अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत स्तर के सभी कर्मी किसानों के बीच आधुनिक फसल तकनीक को हस्तांतरित करें ताकि उत्पादकता में वृद्धि हो सके। मुख्यालय से नामित नोडल पदाधिकारी उप निदेशक, बीज मनोज कुमार द्वारा बीज वितरण पर जानकारी प्रदान की गई। जिला कृषि पदाधिकारी बक्सर ने बताया कि इस वर्ष रबी फसल हेतु एक लाख पंद्रह हजार हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित है। इस निमित्त सभी प्रसार कर्मी बीज वितरण के पश्चात किसानों को तकनीकी जानकारी प्रदान करते हुए लक्ष्य को हासिल कर अधिक से अधिक उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाए। उन्होंने सभी प्रसार कर्मी

को हिदायत दी कि फसल अवशेष प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान दें। किसी भी स्तर पर लापरवाही बरतने पर संबंधित कर्मी पर कार्रवाई की जाएगी। वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र, बक्सर डॉ. देवकरण द्वारा रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसलों पर जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि फसल के उत्पादकता हासिल करने हेतु तकनीकी हस्तांतरण मुख्य कारक है। कार्यक्रम में प्लांट मूडिंग विशेषज्ञ हरगोविंद जायसवाल, सहायक निदेशक (प्रक्षेत्र) रोखर किशोर, सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण) आशीष कुमार, सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण) बेबी कुमारी सहित संबंधित विभागीय पदाधिकारी द्वारा तकनीकी जानकारी प्रदान की गई। (जगत फीचर्स)

सम्पादकीय अमेरिका में कमला हैरिस की हार नहीं यह प्रवासी भारतीयों की उम्मीदों की भी हार है

अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव विश्व राजनीति में अत्यधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है। इन चुनावों में राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति पद पर काबिज नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो देश की नीतियों और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को आकार देती है। कमला हैरिस, अमेरिका की पहली महिला, पहली अश्वेत और पहली एशियाई मूल की उपराष्ट्रपति बनकर इतिहास रच चुकी हैं। उनके नेतृत्व ने विभिन्न मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया और नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। हालांकि, उनकी चुनौतियाँ और राजनीतिक गतिशीलता ने चुनावी परिणामों पर खास असर डाला, जिसके कारण उनकी राजनीतिक सफलता सुनिश्चित नहीं हो सकी।

कमला हैरिस का राजनीतिक सफर कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल के रूप में शुरू हुआ, जहाँ उन्होंने न्याय प्रणाली में सुधार और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर काम किया। इसके बाद, उन्होंने अमेरिकी सीनेट में अपनी जगह बनाई, जहाँ उन्होंने प्रगतिशील नीतियों का समर्थन किया। 2020 में, जो बाइडन के साथ उप-राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से उन्होंने इतिहास रचा। उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में कोविड-19 महामारी के दौरान टीकाकरण कार्यक्रम का समर्थन और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास शामिल हैं। हालांकि, सीमा सुरक्षा और आव्रजन नीतियों से जुड़े विवाद और प्रशासनिक फैसलों की आलोचना भी उनके कार्यकाल में प्रमुख

रूप से देखी गई।

कमला हैरिस की चुनावी हार के प्रमुख कारणों में सबसे बड़ा मुद्दा जनता के बीच अपेक्षित लोकप्रियता की कमी रही। लोग उनके नेतृत्व और निर्णय क्षमता पर संदेह करते रहे, जिससे समर्थन कमजोर पड़ा। इसके अलावा, बढ़ती महंगाई और आर्थिक समस्याओं ने आम जनता में सरकार के प्रति नाराजगी को बढ़ावा दिया। विपक्षी दलों ने अपनी रणनीतियों को मजबूती से लागू किया, जिससे कमला हैरिस और उनकी पार्टी को नुकसान हुआ। डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदरूनी मतभेद और चुनौतियों ने भी चुनावी परिणाम को प्रभावित किया। इन सभी कारकों ने मिलकर उनके चुनावी अभियान की सफलता में बाधा उत्पन्न की।

कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कई नीतिगत विवाद उभरकर सामने आए। इनमें आव्रजन नीति और सीमा सुरक्षा के मुद्दे प्रमुख रहे, जिन पर आलोचकों ने उनकी नीतियों को अपर्याप्त और विफल बताया। इसके अलावा, कोविड-19 प्रतिबंधों और महामारी से जुड़े उपायों पर भी मिश्रित प्रतिक्रियाएँ मिलीं। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी ने उनकी और बाइडन प्रशासन की छवि को गहरा आघात पहुंचाया। इस निर्णय से न केवल घरेलू बल्कि वैश्विक आलोचना भी हुई, जिससे अमेरिकी नेतृत्व की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए। इन नीतिगत विवादों ने उनकी राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर दिया।



सियासी गहमागहमी

भागव और रावत की किस्मत मतपेटी में बंद



मध्यप्रदेश को चर्चित विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गये हैं। दोनों ही सीटों पर भाजपा के दिग्गज नेताओं ने अपनी किस्मत आजमाने के लिये खुद को पूरी तरह से झोंक दिया है। मतदान समाप्ति के साथ ही दोनों ही उम्मीदवार रमाकांत भागव और रामनिवास रावत की किस्मत पूरी तरह से मतपेटी में बंद हो गई है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या रामनिवास रावत विजयपुर और रमाकांत भागव बुधनी विधानसभा सीट पर कोई कमल खिला पाते हैं या फिर एक बार फिर कांग्रेस दोनों ही सीटों पर बाजी मारकर भाजपा को पटखनी देगी। हालांकि सूत्रों की मानें तो दोनों ही सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने जबरदस्त टक्कर दी है और मतगणना के समय स्थिति बहुत ही कांटे की होनी की संभावना है।

सीएम हाउस में पहुंचने की लगी होड़



प्रदेश के अफसरों में सीएम हाउस से प्रदेश के संचालन की व्यवस्था को संभालने की जबरदस्त होड़ लगी हुई है। प्रदेश के नये मुख्य सचिव ने पिछले दिनों जबरदस्त ट्रांसफर कर अपने तेवर दिखा दिये हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जिस प्रशासनिक दृष्टि से थोकबंद ट्रांसफर किये उससे तो यही लगता है कि यह पूरी तैयारी आगामी वर्ष 2029 को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। ऐसे में जैन साहब के आसपास उच्च अधिकारी चक्कर लगाणा आरंभ कर चुके हैं। हर कोई सीएम हाउस में खाली पड़े पदों पर खुद को काबिज करने के लिये लगातार प्रयास कर रहा है।

हपते का कार्टून



ट्वीट-ट्वीट

afe कौन है?

अडानी

1 लाख करोड़ रुपए की धारदाती की जमीन फिसे

मिली?

अडानी को

Unsafe कौन है?

महाराष्ट्र की आम जनता, महिलाएं, किसान, युवा और बहजन।

-राहुल गांधी

काबेस नेता @RahulGandhi



राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

यह दिवस देश में पत्रकारिता के मूल्यों को मजबूत करने की याद दिलाता है। देश में पत्रकारिता और पत्रकारों के सामने आज जैसी चुनौतियाँ हैं, वैसी पहले कभी नहीं थी। हम सबको प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान देना होगा।

-कमलनाथ



प्रेस काबेस अख्य

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

युवाओं के बीच प्रेरक राजनैतिज्ञ के रूप में विशिष्ट पहचान रखते हैं पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस

समता पाठक/जगत प्रवाह



महाराष्ट्र भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस का पूरा नाम देवेन्द्र गंगाधर फडणवीस है। वह भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक सक्रिय राजनेता हैं। वह महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री हैं। 22 जुलाई 1970 को नागपुर, महाराष्ट्र में ब्राह्मण परिवार में फडणवीस पैदा हुए। वह 44 वर्ष की उम्र में शरद पवार के बाद महाराष्ट्र के सबसे छोटे मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 31 अक्टूबर, 2014 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सीएम पद की शपथ ली। फडणवीस ने नागपुर में सरस्वती विद्यालय, शंकर नगर चौक से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है। उन्होंने पांच साल की एकीकृत कानून की डिग्री के लिए नागपुर के सरकारी लॉ कॉलेज में दाखिला लिया और 1992 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बिजनेस मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर डिग्री और डीएईई, बर्लिन से परियोजना प्रबंधन में डिप्लोमा लिया हुआ है। देवेन्द्र फडणवीस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और 1990 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए। उन्होंने नागपुर के राम नगर वार्ड से अपना पहला नगरपालिका चुनाव जीता और 1992 में, 22 साल की उम्र में, सबसे कम उम्र के पार्षद के रूप में चुने गए। वर्ष 1997 में, वे नागपुर नगर निगम के सबसे कम उम्र के मेयर और भारत के दूसरे सबसे कम उम्र के मेयर बने। साल 1999 से 2004 तक उन्होंने लगातार तीन बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया।

फडणवीस को 2001 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2010 में भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के महासचिव के रूप में कार्य किया और 2013 में राज्य इकाई के अध्यक्ष बने। 2019 में नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से उन्हें देबा रा अभ्यक्ष चुना गया। एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ गठबंधन करने के बावजूद विधानसभा में बहुमत साबित करने में विफल रहने के कारण शपथ लेने के तीन दिन बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

देवेन्द्र फडणवीस के पास कानून की डिग्री है। लेकिन उन्होंने कभी कानून का पालन नहीं किया। वह एबीवीपी के सक्रिय सदस्य थे और युवाओं को समाज के पुनर्निर्माण की दिशा में प्रसारित करते थे। वह दीवारों को पेंट करते थे और राजनेताओं के प्रचारक पोस्टर चिपकाते थे। देवेन्द्र फडणवीस ने अग्रएसएस से अपना कैरियर शुरू किया था। वह 22 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम के मेयर बने थे। वह अपने बौद्धिक कौशल और पेशेवर अखंडता के लिए जाने जाते हैं। 2002-03 में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ द्वारा देवेन्द्र फडणवीस को सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्वर्गीय प्रमोदजी महाजन की स्मृति में उन्हें सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार मिला। उन्हें प्रणव परिवार, नासिक द्वारा राजयोगी नेता पुरस्कार से सम्मानित किया।

पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और पुनर्स्थापन वैश्विक आवश्यकता है



पर्यावरण की फिक डॉ. प्रकाश सिन्हा पर्यावरणविद्

पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण और पुनर्स्थापन आज के दौर में एक गंभीर वैश्विक आवश्यकता बन चुका है। बढ़ती आबादी, औद्योगिकीकरण, और मानवीय हस्तक्षेप के चलते प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से क्षरण हो रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा उन सभी जीवित और निर्जीव घटकों के बीच पारस्परिक संबंधों की एक समग्र प्रणाली है, जो पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाए रखती है। इसके संरक्षण

सकते हैं। इनमें मुख्यतः हैं वनों का कटाव, पानी का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, टिकाऊ विकास, पुनर्स्थापन के प्रयास आदि। वनों का कटाव पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का प्रमुख कारण है। वृक्षारोपण और वनों की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही, वन्यजीवों के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना भी आवश्यक है। इन संसाधनों का जिम्मेदाराना उपयोग और पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) नीतियों को अपनाना चाहिए। जलाशयों और नदियों के प्रदूषण को रोकना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ होती है। विभिन्न प्रजातियों के अस्तित्व के लिए उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल भंडार, और अभयारण्य इसके उदाहरण हैं। औद्योगिक गतिविधियों को ऐसे ढंग से अंजाम देना जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो। हरित ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और जल विद्युत का उपयोग पारंपरिक ईंधनों की तुलना में कम प्रदूषणकारी होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्स्थापन उसके क्षतिग्रस्त भागों को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह न केवल पर्यावरण को संतुलन में लाने में मदद करता है बल्कि सामुदायिक विकास और आर्थिक सुधार में भी सहायक होता है। जंगलों की कटाई से जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए बड़े पैमाने पर नए जंगलों का निर्माण करना। यह जलवायु को स्थिर रखने में मदद करता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करता है। उन क्षेत्रों में सुधार करना जहाँ अति-उपयोग या प्रदूषण के कारण मिट्टी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हुआ है। जैविक खेती और प्राकृतिक उर्वरकों का प्रयोग इस दिशा में सहायक होता है। तालाबों, नदियों, और झीलों की सफाई और पुनर्जीवन के माध्यम से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारा जा सकता है। इस कार्य

में स्थानीय समुदायों की भागीदारी आवश्यक होती है ताकि उन्हें अपने संसाधनों के महत्व का अनुभव हो सके। पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण और पुनर्स्थापन को कई चुनौतियाँ हैं। इनमें राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, आवश्यक वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता और लोगों में जागरूकता की कमी प्रमुख हैं। इसके समाधान के लिए कुछ उपायों को अपनाया जा सकता है। सरकारों को पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए। कड़े कानून और नीतियाँ लागू कर पर्यावरणीय अपराधों पर रोक लगानी चाहिए। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोग इसके महत्व को समझें और इसमें योगदान दें। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) के हिस्से के रूप में पर्यावरणीय परियोजनाओं में निवेश करना चाहिए। निजी और सार्वजनिक संगठनों का सहयोग इस दिशा में एक बड़ा अंतर ला सकता है। उन्नत तकनीक जैसे ड्रोन का उपयोग वनों की निगरानी के लिए और जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, सेंसर तकनीक और सॉफ्टवेयर भी प्रदूषण के स्तर की निगरानी में मदद कर सकते हैं।

पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण और पुनर्स्थापन एक सामूहिक प्रयास की मांग करता है। यह केवल सरकारों या गैर-सरकारी संगठनों की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अपनी जीवनशैली में छोटे बदलाव जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग, पुनर्चक्रित उत्पादों का चयन, और कम प्रदूषणकारी परिवहन साधनों का उपयोग भी बड़ा अंतर ला सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और पुनर्स्थापन एक दीर्घकालिक प्रयास है जो न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ जीवन प्रदान करता है।

महिलाओं को पुरुषों के समान मानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण पाने का पूरा अधिकार - डॉ. संदीप सबलोक

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह, सागर। मानव अधिकार अपने उपचारों में लिंग, जाति, वर्ग आदि किसी भी आधार पर मनुष्यों में विभेद नहीं करते हैं। समाज में रहने वाली महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही उनके मानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण पाने का पूरा अधिकार है। यह बात शासकीय कला एवं सांघिक्य महाविद्यालय (अग्रणी) राजनीति विज्ञान विभाग के विद्वान अश्वेता डॉ. संदीप सबलोक ने शासकीय स्वरासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय की छात्राओं की बीच कही। कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ आनंद तिवारी के निर्देशन में राजनीति विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. सुनीता त्रिपाठी द्वारा विभागीय सहयोगी डॉ. प्रह्लाद सिंह के साथ महाविद्यालय की छात्राओं के लिए मानव अधिकार का सर्टिफिकेट कोर्स संचालित किया जा रहा है।



पाठ्यक्रम में करीब 200 पंजीकृत छात्राएँ हिस्सा ले रही हैं। मानव अधिकार सर्टिफिकेट कोर्स में विषय विशेषज्ञ वक्ता के रूप में यहां पहुंचे डॉ. संदीप सबलोक ने अपने व्याख्यान के प्रारंभ में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आनंद तिवारी तथा राजनीति विज्ञान विभाग अध्यक्ष डॉ. सुनीता त्रिपाठी द्वारा मानव अधिकार के सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में महाविद्यालय संचालित करने के लिए उनका साधुवाद किया। अपने व्याख्यान में उन्होंने फ्रांस द्वारा 18वीं शताब्दी में दस प्रथा के खिलाफ शुरू किए गए मानव अधिकारों के संरक्षण तथा 1890 में ब्रिटेन द्वारा दासता विरोधी कानून की स्थापना को मानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में डॉ. सुनीता त्रिपाठी द्वारा कमजोर देश पर अक्रमण करे वहां की जनता को युद्ध की विभीषिका में झोंकने से उत्पन्न परिस्थितियों के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति के साथ मानव अधिकारों की सुरक्षा पर भी बल दिया और 10 दिसंबर 1948

को दुनिया के सभी देशों के लिए मानव अधिकारों की स्थापना की। मानव अधिकारों के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए डॉ. संदीप सबलोक ने अगे कहा कि प्रत्येक मनुष्य के लिए मानव अधिकार महज जन्म से नहीं बल्कि जन्म लेने के पहले से ही शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक मनुष्य को मृत्यु पर्यंत तक अपनी गरिमा और गौरव के अनुरूप मानव अधिकारों को प्राप्त करने का अधिकार है। डॉ. संदीप सबलोक ने छात्राओं के बीच कहा कि दुनिया भर में नारी वर्ग को जन्म लेने और जन्म देने का समान रूप से नैसर्गिक अधिकार है। गर्भवस्था को स्वस्थ रूप में जन्म लेने के लिए गर्भवस्था के दौरान अपनी गर्भवती मां के माध्यम से पोषण आहार व अन्य सुरक्षात्मक उपचार पाने तथा जन्म लेते ही मां का दूध पीने व सुरक्षित लालन-पालन पाने का भी पूरा अधिकार है। लेकिन भारत समेत दुनिया के कई देशों में पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था तथा रुढ़ियों के चलते महिलाएं आज भी अपने मूलभूत मानव अधिकारों से वंचित हैं। (जगत फीचर्स)

मूल्यबोध है हिंदी पत्रकारिता का दार्शनिक आधार: प्रो. संजय द्विवेदी

-संवाददाता

उगत प्रवाह, नई दिल्ली। भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के पूर्व महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी का कहना है कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और मूल्यबोध ही हिंदी पत्रकारिता का दार्शनिक आधार है। हिंदी भाषा नहीं प्रज्वलित है, इसमें अन्याय का प्रतिरोध एक आवश्यक शर्त है। ये वहां भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद और सत्यवती कालेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य वक्ता की आसदी से बोल रहे थे। सत्र की अध्यक्षता दीएवी सांध्य कालेज के प्रो.हरीश अरोड़ा ने की और मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्वमंत्री और साहित्यकार खीन्द्र शुक्ल रहे। प्रो. द्विवेदी ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता और साहित्य का स्वभाव ही है

सत्यवती कालेज में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन

अन्याय के विरुद्ध लड़ना। उन्होंने कहा कि भारतीय संचार परंपरा जोड़ने के सूत्र देती है, उसका उद्देश्य लोक-मंगल है, जबकि नवीन संचार प्रणालियां नकारात्मकता के आधार पर व्यवसाय कर रही हैं। जबकि एक सुंदर दुनिया बनाने के लिए सार्वजनिक संवाद में शुचिता और मूल्यबोध दोनों आवश्यक है। इससे ही हमारा संवाद लोकहित केंद्रित बनेगा। प्रो. द्विवेदी ने कहा कि मीडिया और साहित्य का भारतीय मूल्यों पर खड़ा होना आवश्यक है और समाज का आध्यात्मिकरण जरूरी है। इस अवसर पर सत्यवती कालेज की प्राचार्या डॉ. अंजू सेठ, स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगोष्ठी प्रो. अश्विनी महानज, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी के प्रो.



पुनीत बिसारिया, नर्वे से पथारे साहित्यकार सुरेशचंद्र शुक्ल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रो.सुधीर आर्य ने भी अपने

विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन डॉ. ममता ने किया। (जगत फ्रीप्रेस)

प्रदेश को मिलेगी आर्थिक गति, रोजगार के अवसर सृजित होंगे

(पेज 1 का शेष)
इसके तहत ऐसे उद्योग, जिनमें उत्पादन शुरू नहीं हुआ है व जिनमें किसी तरह की छूट नहीं ली है और उसे किसी दूसरे उद्योगी ने खरीद लिया हो, उसे नई इकाई मानते हुए छूट देने का प्रावधान है।

सर्टिफिकेट करने वाले नक्सलियों को प्रशिक्षण देने पर मता

साथ ही इनमें गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में लगने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन, स्थानीय युवाओं और आत्मसम्पन्न नक्सलियों को नौकरी देने पर उद्योगों को प्रशिक्षण भत्ता, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए फंड, AI और रोबोटिक्स में काम करने वाले उद्योगों को 12 साल के लिए 100% राज्य GST प्रतिपूर्ति और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक विदेशी व्यापार सहायता केंद्र शामिल है।

15,000 रुपए ट्रेनिंग मत्ता

नई नीति के अनुसार, कौशल विकास और निर्यात प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार उन उद्योगों द्वारा काम पर रखे गए प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए 15,000 का प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करेगी जो 1,000 से अधिक स्थानीय श्रमिकों को रोजगार देते हैं, बशर्ते कि कर्मचारी कम से कम 12 महीने तक कार्यरत रहे।

कर्मचारियों के पीएफ का 75 फीसदी कवर करेगी सरकार

इसके अतिरिक्त, नीति में रोजगार के पहले पांच वर्षों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योगदान के 75% को कवर किया गया है। यह नीति राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मददगार साबित होगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। नई औद्योगिक नीति के ड्राफ्ट में 12 वर्षों तक विद्युत शुल्क में छूट देने, भूमि, शोध, भवन की खरीदी पर लगाने वाले स्टार्ट शुल्क में 30 प्रतिशत तक छूट देने का प्रविधान है। पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत तक सरकार छूट देगी। इस नीति में छोटे और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से प्रविधान किए गए हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य पहले ही निवेश आकर्षित करने के लिए 40 प्रतिशत तक छूट दे रहे हैं।

इन चीजों पर सरकार का जोर

नई नीति में कैपिटल कैप की सीलिंग समाप्त करने, नए उद्योगों-पुराने उद्योगों के विस्तार पर छूट देने, फार्मा, टेक्स्टाइल, आईटी जैसे उद्योगों को प्राथमिकता देने,

लाजिस्टिक हब बनाने, एकीकृत औद्योगिक पार्कों की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता, स्टील सेक्टर में वैल्यू एडिशन वाले उद्योगों की स्थापना पर भी जोर दिया गया है।

रोजगार का बहेगा दावरा

नई औद्योगिक नीति के आधार पर यहां निवेश करने का एक बड़ा आकर्षण होगा। यह न केवल राज्य के विकास को तेजी से आगे बढाने में मदद करेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करेगा। इससे प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातावरण का निर्माण होगा और प्रदेश के निवासियों को रोजगार मिलेगा।

अभी राज्य में ये बड़ी कंपनियां

राज्य में लगभग 600 बड़ी कंपनियां चल रही हैं। इसमें से हाल ही में राज्य की छह इकाइयां क्रमशः श्रीवासु लाजिस्टिक लिमिटेड, जैनम फेयरो एलोएस लिमिटेड, केएन एपी रिसॉर्सेस लिमिटेड, अहम टेकनालाजिस लिमिटेड, चमन मेटालिक्स लिमिटेड और एटमस्टको लिमिटेड राष्ट्रीय स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) में सूचीबद्ध हुई हैं। वहीं, देश में लगभग 2,512 कंपनियां एनएसई में पंजीकृत हैं। इनकी कुल बाजार पूंजी करीब 464.38 लाख करोड़ रुपये है।

1000 करोड़ से अधिक निवेश पर विशेष प्रोत्साहन: सेवा श्रेणी के बड़े उद्योगों में स्थाई पूंजी निवेश में 500 करोड़ या इससे अधिक निवेश करने वाली या 1000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

सभी तरह की छूट ऑनलाइन देने पर जोर: नो फिजिकल कांटेक्ट सिस्टम पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की प्रक्रिया को अपनाने पर सरकार का जोर है। इसके लिए ऑनलाइन प्रणाली को पारदर्शी, अधिक सशक्त, समयबद्ध एवं क्रियाशील बनाने सरकार का प्रयास है। सभी तरह के अनुदान या छूट देने की प्रक्रिया को इस सिस्टम से जोड़ा जा सकता है।

बड़े निवेश पर मंत्री मंडलीय उपसमिति लेगी निर्णय: बड़े निवेशकों को राज्य कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज देगी। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी 5 सदस्यीय मंत्री मंडलीय उप समिति निर्णय लेगी। उप समिति में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के मंत्री सदस्य सचिव होंगे। जबकि वित्त और विधि विभाग के मंत्री सदस्य के रूप में होंगे। इसके अलावा जरूरत के अनुसार अन्य विभाग के एक मंत्री विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में समिति की बैठकों में शामिल होंगे।

कैबिनेट बैठक में नई उद्योग नीति को मंजूरी: 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 मंजूरी की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने और राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं। राज्य के प्रशिक्षित व्यक्तियों को

औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए उद्योगों के लिए प्रति व्यक्ति 15 हजार रुपये की स्टार्टअपड नीति 31 मार्च 2030 तक के लिए होगी।

नई औद्योगिक नीति से लाभ: नई औद्योगिक नीति में निवेश प्रोत्साहन में ब्याज अनुदान, लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट, मूल्य संबंधित कर प्रतिपूर्ति का प्रावधान है, नई नीति में मंडी शुल्क छूट, दिव्यांग (नि:शक्त) रोजगार अनुदान, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान, नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति के भी प्रावधान किये गये हैं। इस नीति में राज्य के युवाओं के लिये रोजगार सृजन को लक्ष्य में रखकर 01 हजार से ज्यादा स्थानीय रोजगार सृजन के आधार पर बी-स्पोक पैकेज विशिष्ट क्षेत्र के उद्योगों के लिये प्रावधानित है। राज्य के निवासियों विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों, जिनमें पैरामिलिट्री भी शामिल है, को नई औद्योगिक नीति के तहत अधिक प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। नक्सल प्रभावित लोगों, कमजोर वर्ग, तृतीय लिंग के उद्यमियों के लिये नई औद्योगिक नीति के तहत विशेष प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नई औद्योगिक नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र अंतर्गत एमएसएमई सेवा उद्यम और वृहद सेवा उद्यमों के लिये पृथक-पृथक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। इस नीति में फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाईल, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण और गैर काष्ठ वनोत्पाद (एनटीएफपी) प्रसंस्करण, कम्प्रेस्ड बाँयो गैस, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई), रोबोटिक्स एण्ड कम्प्यूटिंग (जी.पी.यू), आईटी, आई.टी.ई.एस., डेटा सेंटर, जल विद्युत परियोजनाओं, सौर ऊर्जा परियोजनाओं आदि के लिए आकर्षक पृथक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान है। राज्य के कोरवा-बिलासपुर-रायपुर को देश के औद्योगिक मानचित्र में स्थान दिलाने के लिये इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना का प्रावधान है।

महिलाओं को शासकीय नौकरियों में 35% आरक्षण

(पेज 1 का शेष)
इसमें प्रदेश की महिलाओं, बेटियों और बहनों को आगे बढ़ाने और उनके विकास के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश सिविल सेवाओं में महिलाओं को अब 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। यह फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया। अभी तक महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलता था। इससे उन्हें एमपीपीएससी और मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में फायदा मिलेगा। मोहन सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों ने इसकी सराहना भी की है।

उप मुख्यमंत्री ने सुनाया था फैसला

मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में और ज्यादा मौके देने का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% करने का फैसला लिया गया। इस फैसले को लेकर एमपी के डेप्युटी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि अब महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत की जगह 35 प्रतिशत रिजर्वेशन दिए जाने का फैसला लिया गया है। यह नियम मध्य प्रदेश सिविल सेवाओं समेत सभी सरकारी नौकरियों पर लागू होगा।

दूसरे राज्यों के लिये मिसाल बना मध्यप्रदेश

देश के कई राज्यों ने महिला सराशक्तिकरण को लेकर मध्यप्रदेश द्वारा उठाए गए कदमों को सराहा है और अपने राज्यों में लागू भी किया है। लाड़ली बहना योजना के माध्यम से राज्य की लगभग एक करोड़ 29 लाख महिलाओं को मासिक 1250 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में भेजी जा रही है। महिला सराशक्तिकरण की यह अनूठी पहल अन्य राज्यों के अनुकरणीय होकर क्रियान्वित की जा रही है। महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों ने लाड़ली बहना योजना को मूल का पथर मानते हुए अपनाया है।

कुपोषित से सुपोषित तक की सफल यात्रा

लगभग दो दशक पहले तक प्रदेश की पहचान एक कुपोषित राज्य के रूप में हुआ करती थी। अब यह बातें जमाने की बात हो गई हैं। मध्यप्रदेश ने कुपोषण के खिलाफ लंबी और चरणबद्ध लड़ाई लड़ते हुए कामयाबी हासिल की है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 3 वर्ष (NFHS-3) 2005-06 और वर्ष 2019-21 के जारी सर्वेक्षण के तुलनात्मक आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार ने कुपोषण के खिलाफ कितनी ईमानदारी से जंग लड़ी और सफलताएं अर्जित कीं। वर्ष 2005-06 की बात करें तो उन दिनों 60% बच्चे अपनी उम्र के अनुसार कम वजन के होते थे, लेकिन वर्ष 2020-21 में यह अंतर घटकर 33% हो गया है। मध्यप्रदेश को कुपोषण के खिलाफ जंग में मिली इस सफलता के फलस्वरूप देश में तीसरा स्थान प्राप्त हो गया।

पुलिस थानों में विशेष डेस्क और 181 हेलप लाइन

महिला सुरक्षा को अपनी उच्च प्राथमिकता में रखते हुए राज्य सरकार हमेशा गंभीरता से कार्य कर रही है। आपत्कालीन स्थिति या किसी भी तरह के संकट में उनकी सहायता के लिए राज्य के सभी 57 जिलों में वन स्टॉप केंद्र संचालित हैं। साथ ही 181 हेलपलाइन नंबर की सेवा प्रदाय की जा रही है। मध्यप्रदेश में महिलाओं को सफल, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला सराशक्तिकरण योजना के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।

(पेज 1 का शेष)

इनकी अधिकारवादी और अधिनायकवादी प्रवृत्ति संघ को काफी चुभी और 2019 के बाद ये और पीड़ा देने लगी। मोदी अपने आपको पार्टी और संघ से उपर मानने लगे। शायद यही कारण है कि आज मोदी संघ के लिए किंकरि बने हुए हैं। वर्तमान में जिस विचारधारा पर संघ चला है या चल रहा है उसमें अब मोदी फिट नहीं बैठ रहे हैं। या कहे कि अपने आप को फिट नहीं बिठाना चाहते हैं। ऐसे तमाम अवसर आये हैं जब मोदी ने संघ की विचारधारा से इतर काम किये हैं। जिसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उन्हें विचारधारा से बढ़कर प्रधानमंत्री की कुर्सी दिख रही हो। खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तो स्थितियाँ और बदल गई हैं। मोदी को स्पष्ट जगह देनी मिली और मोदी का कद कम हो गया। 2024 के परिणामों से संघ काफी आहत हुआ। भारत की राजनीति में एक यह नया अध्याय है जब आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे के आमने-सामने आकर खड़ी हो गई है। कहने वाले तो यह कहते हैं कि यह दोनों एक ही है लेकिन इन दोनों बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है कि इस वक्त फैसले पर आकर अटक गई है और ना ही निकल पा रही है। यहाँ पर मोदी और अमित शाह बीजेपी को पूरी तरह से कंट्रोल कर चुके हैं। उनके चंगुल से बाहर निकलने के लिए आरएसएस ने एक ऐसा दावा खोल दिया है जिसको किसी भी तरह से मोदी और अमित शाह अपसेट नहीं कर पा रहे हैं। वह नहीं चाहते हैं कि आरएसएस इस तरह से दाब खेले कि मोदी और अमित शाह चाणक्य बुद्धि वाले यह दोनों व्यक्ति देखते रह गए हैं। मोदी और अमित शाह के कारण बड़ी परेशानियाँ उठ रही हैं। बीजेपी को प्रेसिडेंट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ऐसे सामने नाम आ गए हैं जिसे सुनकर अमित शाह और मोदी के कानों से धुआँ निकलने लगा है। मोदी और अमित शाह दिन रात सो नहीं पा रहे हैं। वह अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनकी हालत खराब कर दी है बीजेपी को एक ऐसी दशा में ले जाना शुरू कर दिया जो संघ के मूल सिद्धांत और विचारधारा से मेल नहीं खाती।

आईये सबसे पहले हम उन नामों के विषय में जानते हैं जिन पर संघ भरोसा जता रहा है। और संघ की पसंद बने हुए हैं।

संजय जोशी: संघ की पहली पसंद

आज दरअसल कहानी उस इंसान की शुरू करना चाहूँगी जिसकी कहानी अभी सच में बाकी है। वह इंसान ऐसा है जिससे शायद इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा घबराते हैं। जिसके नाम का खीफ फिलहाल मोदी जी के दिल में बैठ गया है और उस शख्स का नाम है संजय जोशी। संघ उन्हें वापस पार्टी की मुख्य धारा में लाना चाहता है। संघ चाहता है कि संजय जोशी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाये। भाजपा में सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी संजय जोशी अपना मित्र और मार्गदर्शक मानते हैं क्योंकि वह सरल और निरहंकारी हैं। लोगों से सहज ही आत्मनियता स्थापित कर लेते हैं। कुशल संगठक के जो आवश्यक गुण होते हैं वे संजय जोशी में देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को महत्वपूर्ण दायित्व मिलता है तो उस संस्था के लिये अनमोल सहयोग होगा।

यह भी सच है कि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी का 36 का आंकड़ा है। यह 36 का आंकड़ा तबसे है जब गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। संजय जोशी को गुजरात से और पार्टी से बाहर करने में मोदी का ही बहुत बड़ा रोल रहा है। हालाँकि उस समय मोदी को संजय जोशी को बाहर करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। अगर संजय जोशी बीजेपी में किसी पोजीशन पर आ जाते हैं, अध्यक्ष पद पर आ जाते हैं तब तो मोदी जी के लिए 05 साल पूरे करना मुश्किल होगा। दरअसल संजय जोशी के विषय जानना जरूरी है। संजय जोशी संघ के

संघ चाहता है संजय जोशी, प्रवीण तोगड़िया और योगी आदित्यनाथ में से कोई एक बने बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष

प्रचारक थे और संघ के लिए काम करते थे लेकिन संघ को उनमें कुछ क्वालिटी नजर आई तो संघ ने उन्हें कहा कि आप बीजेपी ज्वाइन कीजिए। फिर उन्हें 1989 में गुजरात भेजा गया। स्पेशल जिम्मेदारी लेकर भेजा गया क्योंकि गुजरात में उस वक्त भाजपा कमजोर थी और संजय जोशी की खासियत थी कि वह ग्रास रूट वर्कर से मिलकर ग्रास रूट लेवल पर पार्टी को मजबूत करते थे। 1988 में जब वे गुजरात पहुंचे उसके बाद उन्होंने गुजरात में सचिव के रूप के तौर पर काम किया। उस वक्त जोशी ने पार्टी को मजबूत किया। भाजपा सत्ता में आई। गुजरात में मुख्यमंत्री के लिए दो दावेदार थे केशु भाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला। उस वक्त संजय जोशी और नरेंद्र मोदी दोनों ने केशु भाई पटेल का समर्थन किया। पटेल मुख्यमंत्री बन गए। पटेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद शंकर सिंह वाघेला ने विद्रोह कर दिया। नरेंद्र मोदी पर विद्रोह की गज गिरी। उन्हें गुजरात से दिल्ली भेज दिया गया लेकिन संजय जोशी गुजरात में रहे और जैसे ही नरेंद्र मोदी दिल्ली गये, उसके बाद संजय जोशी और मजबूत हो गए। मोदी गुजरात आना चाहते थे। गुजरात में काम करना चाहते थे, गुजरात में किसी भी तरह से घुसना चाहते थे पैठ बनाना चाहते थे लेकिन कहा यह जाता है कि जब-जब उन्होंने गुजरात में जाने की कोशिश की संजय जोशी ने उनका रास्ता काटा। गुजरात में मोदी की एंट्री नहीं होने दी। मोदी को यह बात कहीं ना कहीं दिल में बैठ गई। और फिर वक्त आता है पार्टी केशु भाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाती है और 2002 में नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाकर गुजरात भेजती है। नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचते ही तो उनके निशाने पर सबसे पहले आते हैं संजय जोशी। नरेंद्र मोदी चाहते थे कि किसी भी तरह से संजय जोशी को दिल्ली भेजा जाए, गुजरात से बाहर किया जाए। इसी बीच वर्ष 2005 में गुजरात में एक सीडी कांड होता है। जिसमें संजय जोशी को फंसाया जाता है। और संजय जोशी को गुजरात से बाहर जाने पर मजबूर किया जाता है। बात 2011-12 के आसपास की है, जब 05 साल राजनीति से दूर रहने के बाद संजय जोशी ने तबके बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी से संपर्क किया। गडकरी से कहा कि मैं पार्टी के लिए कुछ करना चाहता हूँ और नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी लेकिन उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। वहीं नरेंद्र मोदी, संजय जोशी को सिर्फ गुजरात से ही बाहर नहीं करना चाहते थे वह तो संजय जोशी को पार्टी से ही बाहर करना चाहते थे। 2013 में मुंबई में बीजेपी का महाअधिवेशन था। नितिन गडकरी अध्यक्ष थे। अधिवेशन के एक दिन पहले मोदी ने शर्त रख दी कि अगर संजय जोशी नेशनल एजीक्यूटिव से इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक मैं इस अधिवेशन में नहीं आऊँगा। इस तरह एक मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को चैलेंज किया था। नितिन गडकरी ने मजबूरी में संजय जोशी से इस्तीफा देने को कहा और संजय जोशी ने इस्तीफा दे दिया। यह बात मोहन भागवत को भी अच्छी नहीं लगी। राजनाथ सिंह को भी पसंद नहीं आयी थी।

संजय जोशी को इस तरह से बाहर करना क्योंकि संजय जोशी ऐसे कार्यकर्ता हैं जो संगठन के लिए काम करते हैं। उसके बाद मोदी प्रधानमंत्री बन गए। इसके बाद संजय जोशी गायब ही रहे। संजय जोशी को पार्टी के अंदर बहुत लोगों का सपोर्ट है, संघ का सपोर्ट है। नितिन गडकरी का सपोर्ट है, राजनाथ सिंह का भी सपोर्ट है। लेकिन अब समय बदला है। संघ संजय जोशी को पुनः लाना चाहता और इसमें अंदर ही अंदर नितिन गडकरी राजनाथ सिंह के साथ-साथ योगी आदित्यनाथ का भी सपोर्ट है। हालाँकि अभी संजय जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में नोटबंदी और राम मंदिर को लेकर स्टेटमेंट भी दिया है। लेकिन मोदी को गले नहीं उतरी। आज भी मोदी संजय जोशी को एक आंध नहीं देखना चाहते। अब पूंसे में जबसे यह बात चली है कि संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं तो मोदी को लगता है कि क्या यह मुमकिन है। संजय जोशी आईआईटी से इंजीनियर हैं। और बहुत ही विद्वान हैं।

प्रवीण तोगड़िया: हिंदुत्व के प्रखर पुरोधा

प्रवीण तोगड़िया कुशल संगठक, श्रेष्ठशाली और भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति का किसी संस्था को मिलना उस संस्था के लिए लाभदायक होगा। प्रवीण तोगड़िया ने सारा जीवन संगठन खड़ा करके एक विशाल प्रतिबद्ध विचारधारा से व्यक्ति निर्माण का अद्भुत निर्माण किया है। देश को नेतृत्व देने लायक व्यक्ति समाज को प्रदान किये ऐसा व्यक्ति भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए तो संस्था के लिये अपरिमित लाभकारी होगा। संस्कृति समाज व देश के लिये स्वर्णिम अवसर होगा। जैसे संघ भी चाहता है कि प्रवीण तोगड़िया को पसंद कर रहा है। और चाहता है कि तोगड़िया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनें।

विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे प्रवीण तोगड़िया ने करीब तीन दशक तक विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहने के बाद 2018 में प्रवीण तोगड़िया ने इस्तीफा देकर संघ से भी नाता तोड़ लिया था। नई बीजेपी के दौर में अपनी पूछ घटने से प्रवीण तोगड़िया बेहद नाराज थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता अमित शाह के विरोधी माने जाने लगे थे। जब कोई रास्ता नहीं सुझा तो संघ से भी नाता तोड़ कर प्रवीण तोगड़िया ने अलग राह फकड़ ली और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के नाम से नया संगठन बना लिया। बीच-बीच में प्रवीण तोगड़िया को लेकर कई तरह की चर्चाएँ और विवाद भी हुए, लेकिन उनको सबसे ज्यादा तकलीफ तब हुई जब जनवरी 2024 में राम मंदिर उद्घाटन के लिए उनको नहीं बुलाया गया। ध्यान रहे विश्व हिंदू परिषद ने ही अयोध्या में राम मंदिर बनाने का आंदोलन शुरू किया था। पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का नागपुर में मुलाकात भी हुई। प्रवीण तोगड़िया का दावा है कि दोनों मिलकर हिंदू समाज को एकजुट करना चाहते हैं। प्रवीण तोगड़िया और मोहन भागवत की मुलाकात ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। लंबे अर्से बाद ये मीटिंग ऐसे माहौल में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी नेतृत्व के बीच सबकुछ ठीक न होने की

जोरदार चर्चा हो। मुलाकात के बाद प्रवीण तोगड़िया का कहना है, राम मंदिर निर्माण दशकों से बीजेपी के चुनावी वादे का हिस्सा रहा है, लेकिन पार्टी इसका चुनावी फायदा नहीं उठा सकी और 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद से सबसे कम सीटों पर सिमट गई है। प्रवीण तोगड़िया असल में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार की तरफ इशारा कर रहे हैं। यूपी की हार और हरियाणा में जीत को भी संघ के असहयोग और सहयोग से जोड़ कर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके पिछले 15 वर्षों से तनावपूर्ण संबंधों पर चर्चा शुरू हो गई। सूत्रों ने बताया कि एक वक्त ऐसा भी था जब पीएम मोदी और तोगड़िया गहरे दोस्त हुआ करते थे और दोनों एक ही स्कूटर से आरएसएस कार्यकर्ताओं से मिलने जाया करते थे। हालाँकि वर्ष 2002 में मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री बनते ही दोनों के संबंधों में कड़वाहट आ गई। मेडिकल स्टूडेंट प्रवीण तोगड़िया की दिलचस्पी पहले से ही हिंदुत्व के गौरव और प्रचार पर थी। उनकी इसी विचारधारा के कारण वो संघ में चले गए थे, जहाँ उनकी मुलाकात नरेंद्र भाई मोदी से हुई थी। 1980 के दशक की शुरुआत से वो दोस्त बन गए थे। विचारधारा एक होने के चलते मोदी और तोगड़िया की दोस्ती मजबूत हो गई थी। 1985 में अहमदाबाद में सांप्रदायिक उन्माद शुरू हुआ तो प्रवीण तोगड़िया को विश्व हिंदू परिषद की जिम्मेदारी दी गई। सांप्रदायिक उन्माद के दौरान हिंदू पीड़ितों की मदद करने के अलावा प्रवीण तोगड़िया ने और भी जिम्मेदारियाँ उठाईं। तोगड़िया परिषद में थे और मोदी संघ में थे। लेकिन उनका हर क्रमद एक साथ और एक ही दिशा में होता था। तोगड़िया ने गुजरात में बीजेपी के लिए काफी काम किया है। ऐसे व्यक्ति को मोदी ने गुजरात से बाहर का रास्ता दिखाया। मोदी तोगड़िया के नाम पर भी ऐतराज जता रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ: हिंदुत्व का नया चेहरा बनकर उभरे

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चल रहा है। आरएसएस इनके नाम पर भी विचार कर रहा है। क्योंकि इसके कई कारण सामने आ रहे हैं। पब्लिक कारणा तो यह है कि योगी आदित्यनाथ वर्तमान में हिंदुत्व का नया चेहरा बनकर उभरे हैं। ऐसे तमाम अवसर आये हैं जब योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व की रक्षा और संरक्षण की दिशा में कदम उठाये हैं। योगी आदित्यनाथ का रिश्ता मोदी और शाह के साथ कैसा है। पता लगाया जा सकता है कि कितनी बार कोशिशों से हुई कि योगी आदित्यनाथ कौन की कुर्सी से हटाय जा सके। अपने खास लोगों को भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगा दिया लेकिन उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। लेकिन अब संघ ने एक ऐसा रास्ता सुझा दिया है जिससे कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी बचाने का मौका मिल सकता है बल्कि कुर्सी के बदले कुर्सी मिल सकती है। योगी आदित्यनाथ ने उभरते हुए अपने आप को साबित किया है। संगठन से लेकर सरकार तक उन्हे अपनी छाप छोड़ी है। किसी विशेष समुदाय वर्ग से भेदभाव किये बिना प्रदेश को साफ सुथरा किया है। धार्मिक उन्माद मचाने वालों को उन्होंने बखशा नहीं है। संघ की पसंद का शायद यही कारण हो सकता है कि उनमें सबको साधक चलने की क्षमता है, कबिलियत है। हालाँकि योगी के विरोधी भी पार्टी और संगठन में बहुत हैं। जो नहीं चाहेंगे कि योगी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनें।

अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संघ की पसंद चलती है या मोदी एंड कंपनी की चलती है। क्योंकि इस पद के लिए काफी माथापच्ची होनी वाली है। संघ की दरखलअंदाजी से मानकर चला जा सकता है कि यह राह इतनी आसान नहीं होने वाली है।

कलम के सिपाही...

भारत के शीर्ष 50
पत्रकारों में से एक हैं
अंशुमान तिवारी



अंशुमान तिवारी वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया टुडे समूह की इंडिया टुडे पत्रिका के संपादक हैं। वह दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख और उप संपादक थे। उन्होंने डेटन न्यूज और फाइनैशियल टाइम्स, लंदन के साथ दुनिया भर में युमिंग के एक तत्व के रूप में काम किया है। उनके ब्लॉग अर्थात् को आईटीबी द्वारा सर्वश्रेष्ठ हिंदी ब्लॉग की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया। अंशुमान तिवारी का जन्म 25 मार्च 1974 को उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय और भारतीय विद्या भवन, कानपुर से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उनके पास हिंदी/अंग्रेजी साहित्य, भूगोल, एम.ए., भूगोल और हिंदी साहित्य में बी.ए. की डिग्री है, और मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता में मास्टर डिप्लोमा में एक पेशेवर डिग्री है। 1990 के दशक की शुरुआत में कानपुर में, उन्होंने स्टिक एक्सचेंज के स्ट्रिगर के रूप में अपना करियर स्थापित किया। संवाददाताओं से लेकर एक लेखक तक, उन्होंने विभिन्न आर्थिक मंत्रालयों को अपनाया है और अपने पूरे करियर में व्यापक आर्थिक, चाणुजिक और वित्तीय बाजार रिपोर्ट को कई मॉडलों में पेश किया है। वह राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख - दैनिक जागरण के पद पर दिल्ली सैडब्ल्यूजी कॉमनवेल्थ गेम्स 2012 की तीन साल की प्रदर्शनी सहित अपनी संपत्ति के लिए बहुत अधिक हाई-प्रोफाइल समाचारों के साथ एक प्रमुख खोजी स्तंभकार हैं। अंशुमान को नई दिल्ली में इंडिया टुडे पत्रिका के संपादक के रूप में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। इससे पहले, वह 2008 से 2013 तक दैनिक जागरण (भारत का सबसे अधिक आबादी वाला हिंदी दैनिक समाचार पत्र) के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख, ब्यूरो प्रमुख और समूह योगदान प्रमुख और उप संपादक थे। तिवारी डिजिटल हिंदी आर्थिक सामग्री साइट, मनी भास्कर के प्रधान संपादक थे। बीबी कोर्प के स्वामित्व में वह नियमित रूप से दैनिक समाचार पोर्टल डालियो (इंडिया टुडे) के लिए अंग्रेजी में लिखते हैं। हिंदी में एक विश्लेषक के रूप में, वे 15 वर्षों से दैनिक जागरण में साप्ताहिक क्रॉनिकल अर्थ/अर्थ में लिख रहे हैं। अंशुमान एक आर्थिक व्याख्याकार और स्तंभकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में, उन्होंने दैनिक भास्कर समूह के लिए अभिनव और मालिकाना बहुभाषी सामग्री, पहला डिजिटल वर्डकल डिजाइन और निर्मित किया है। उन्हें खोजी पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला है। एक मीडिया रिसर्च के अध्ययन में पाया गया कि अंशुमान भारत के शीर्ष 50 पत्रकारों में से एक हैं। हिंदी पत्रकारिता में उनके योगदान के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन पुरस्कार 2013 मिला।

सतगुरु नानक प्रगट्या, मिटी धुंध जग चानन होया...



आज की
बात
प्रवीण
कवकड
स्वतंत्र लेखक

सेवा और समर्पण का संदेश देता है गुरु नानक जयंती पर्व प्रवीण कवकड कल्पना कीजिए, एक अंधेरे कमरे में अचानक एक दीपक जल उठे। अंधेरा छंटने लगता है और हर कोने में उजाला फैल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ जब गुरु नानक देव जी इस संसार में प्रकट हुए। उनके आगमन से अंधकार को चीरती हुई ज्ञान की किरणें बिखर गईं। सतगुरु नानक प्रगट्या, मिटी धुंध जग चानन होया... ये पंक्ति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले

थी। गुरु नानक देव जी सिर्फ एक धार्मिक गुरु ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान संत, दार्शनिक और समाज सुधारक भी थे। उनके उपदेशों ने लाखों लोगों के जीवन



को बदल दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि सभी मनुष्य एक हैं और हमें एक दूसरे से प्रेम और भाईचारा रखना चाहिए। गुरु नानक जयंती सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जब हम गुरु जी के जीवन और उपदेशों पर चिंतन करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन में सच्चाई, न्याय और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल, 1469 को तलवंडी (अब ननकाना साहिब, पाकिस्तान) में हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक, गुरु नानक देव जी ने मानवता के लिए अनेक मूल्यवान शिक्षाएं दीं। उनकी शिक्षाओं ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। गुरु नानक जयंती, जो कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है, सिख धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। इस वर्ष गुरु नानक जयंती 15 नवंबर, 2024 को मनाई जा रही है।

गुरु नानक देव जी ने अपने पूरे जीवन में यात्रा की और लोगों को एकता, भाईचारे और ईश्वर के प्रति प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने सिख धर्म की नींव रखी और 'गुरु ग्रंथ साहिब' की रचना की, जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है।

गुरु नानक देव जी की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं एकता: सभी मनुष्य एक हैं, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या देश के हों।

कर्म: कर्म ही जीवन का सार है। अच्छे कर्मों से जीवन सफल होता है।

निरंकार: ईश्वर निरंकार है और सभी में व्याप्त है।

संतोष: जो व्यक्ति संतोषी होता है, वह हमेशा सुखी रहता है।

सेवा: दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है।

"नाम जपो, किरत करो, और बंड छको।"

गुरु नानक देव जी ने हमें सेवा का महत्व सिखाया। उन्होंने कहा था, "नाम जपो, किरत करो, और बंड छको।" यानी नाम जपते

रहो, कर्म करते रहो और दूसरों के साथ बांटते रहो। गुरु नानक जयंती इस शिक्षा को याद दिलाने का एक सुनहरा अवसर है। हम अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे कि किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम में जाकर सेवा कर सकते हैं, जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े दान कर सकते हैं, या फिर किसी बीमार व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी ने प्रकृति के महत्व पर भी जोर दिया था। हम पेड़ लगाकर, पानी बचाकर और प्लास्टिक का उपयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। गुरु नानक जयंती केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह प्रेरणा और सेवा का पर्व है। इस दिन हम गुरु नानक देव जी को याद करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए, हम सभी मिलकर गुरु नानक देव जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। आइए, हम सभी मिलकर एकता, भाईचारे और सेवा का संदेश फैलाएं।

स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह, टिमरनी। सामाजिक संस्था नर्मदा जीवन दायिनी एवं चिकित्सा संस्थान नर्मदा ट्रीमा सेंटर, भोपाल व नर्मदा अपना अस्पताल नर्मदापुरम के चिकित्सकों की टीम के द्वारा टिमरनी के पूर्व विधायक संजय शाह टीम "संजय शाह मित्र मंडल टिमरनी व न्यू एस वी एस कबड्डी क्लब के सीजन्य से एक विशाल न्यूरो व हड्डी एवं जोड़ रोग शिविर का आयोजन टिमरनी में शर्मा पाली क्लीनिक अग्रवाल कॉलोनी में किया गया। शिविर में 160 नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाई वितरित की गई।



साथ ही इस शिविर में न्यूरो एवं स्पाइन सर्जन डॉ. सीरभ श्रीवास्तव व ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. देवेश कुमार ने मरीजों की विभिन्न समस्याओं का निदान किया। साथ ही शिविर में टिमरनी के पूर्व विधायक संजय शाह, भाजपा हरदा

जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा, टिमरनी नगर पालिका अध्यक्ष देवेन्द्र भारद्वाज, चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश सहसंयोजक डॉ. सुमित मीड़, चिकित्सा प्रकोष्ठ हरदा मंडल अध्यक्ष डॉ. संजय शर्मा, डॉ. रितेश अग्रवाल, पार्षद सुनील दुबे, पार्षद गुलशन चौरसिया, पार्षद सुधीर गौर, चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक राजेन्द्र शर्मा, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चे के जिला अध्यक्ष राधेश्याम गौर, डॉ. प्रणय शर्मा, भाजपा खेल प्रकोष्ठ के जिला सहसंयोजक अंकित जोशी, अनिल किरार, राजकुमार चंदेल, न्यू एसवीएस कबड्डी क्लब के सभी कबड्डी के खिलाड़ियों सहित नगर के गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। शिविर में सैकड़ों लोगों को परामर्श दिया गया। (जगत फीचर्स)